

3 हरिद्वार कुंभ के लिए 115.61 करोड़ स्वीकृत

5 संगठन, समर्पण और राष्ट्रवाद का सशक्त चेहरा

6 आलेख: भारत की बढ़ती परमाणु शक्ति

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 17 अंक : 06

प्रति सोमवार, 15 जून 2026

मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

मध्यप्रदेश राज्यसभा सीट पर मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द को लेकर उठे सवाल: गलती, साजिश या राजनीतिक रणनीति?

कवर स्टोरी
-विजया पाठक
एडिटर

मध्यप्रदेश में राज्यसभा की एक सीट को लेकर चल रही राजनीतिक हलचल ने कांग्रेस पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह चर्चाओं को तेज कर दिया है। पूर्व सांसद और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र को लेकर सामने आई तकनीकी आपत्तियों और उसके रद्द होने की चर्चा ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक गलियारों में इसे केवल एक साधारण "दस्तावेजी त्रुटि" मानने के बजाय इसे पार्टी के आंतरिक समीकरणों, रणनीतिक निर्णयों और संभावित गुटबाजी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, अब तक इस पूरे मामले में किसी भी



स्तर पर आधिकारिक रूप से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि नामांकन रद्द होने का मूल कारण क्या था। क्या यह केवल कागजी गलती थी या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक प्रक्रिया काम कर रही थी। इसी अस्पष्टता ने इस मुद्दे को और अधिक संवेदनशील और चर्चित बना दिया है।

नामांकन रद्द होने की प्रक्रिया पर उठे सवाल

सूत्रों के अनुसार, मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन पत्र में कुछ तकनीकी खामियां सामने आईं, जिनके आधार पर चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया। हालांकि, यह दावा किया जा रहा है कि नामांकन दाखिल करते समय वरिष्ठ विधि विशेषज्ञों और कांग्रेस के अनुभवी नेताओं की देखरेख मौजूद थी। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठ रहा है कि आखिर इतनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में गलती कैसे रह गई। (शेष पेज 2 पर)

नीति आयोग की बैठक में छत्तीसगढ़ मॉडल की गूंज

CM विष्णुदेव साय ने रखा समावेशी विकास का विजन

-विजया पाठक

नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गर्वनिंग काउंसिल की बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के विकास, सुरासन, कृषि उन्नयन, जनजातीय कल्याण, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल प्रशासन से जुड़े विभिन्न विषयों पर राज्य का पक्ष प्रभावी ढंग से रखा। बैठक में मुख्यमंत्री ने विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल और राज्य सरकार द्वारा संचालित

विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों, कृषि उत्पादन, वन संपदा और जनजातीय संस्कृति से समृद्ध राज्य है। राज्य सरकार का लक्ष्य इन संसाधनों का संतुलित उपयोग करते हुए विकास की ऐसी संरचना तैयार करना है, जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने बताया कि राज्य में सुरासन, पारदर्शिता और त्वरित सेवा वितरण को प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख आधार बनाया गया है।

किसानों को केंद्र में रखकर विकास की रणनीति

नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री साय ने कृषि क्षेत्र को राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए किसानों के हित में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर रही है। धान खरीदी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है तथा किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। (शेष पेज 2 पर)



जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की



आवास से उद्योग तक, विकास की अनेक कहानियों के नायक कमलनाथ

मप्र और राष्ट्रीय राजनीति का अनुभवी चेहरा और विकास का विश्वसनीय नाम

-विजया पाठक

भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे नेता होते हैं जिनकी पहचान केवल चुनावी सफलताओं या राजनीतिक पदों से नहीं, बल्कि उनके द्वारा किए गए जनकल्याणकारी कार्यों और दूरदर्शी सोच से बनती है। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ऐसे ही नेताओं में शामिल हैं। लगभग पांच दशकों के सार्वजनिक जीवन में उन्होंने केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं और विकासोन्मुख राजनीति का एक अलग उदाहरण प्रस्तुत किया। कमलनाथ का राजनीतिक जीवन केवल एक संसदीय क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। लंबे समय तक केंद्र सरकार में विभिन्न मंत्रालयों का दायित्व संभालते हुए उन्होंने उद्योग, वाणिज्य, सड़क परिवहन,

पर्यावरण और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी कार्यशैली का सबसे बड़ा गुण यह रहा कि वे योजनाओं को केवल कागजी तक सीमित रखने के बजाय उन्हें धरातल तक पहुंचाने में विश्वास रखते थे। गरीबों के लिए आवास, औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विस्तार और छिंदवाड़ा जैसे क्षेत्र को विकास का मॉडल बनाना उनकी सार्वजनिक जीवन की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं। राजनीतिक मतभेदों से परे यह स्वीकार करना होगा कि कमलनाथ ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में विकास को राजनीति का केंद्र बनाने का प्रयास किया। यही कारण है कि समर्थकों की दृष्टि में उनका योगदान केवल कांग्रेस तक सीमित नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश और देश के विकास की व्यापक यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। (शेष पेज 3 पर)

मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द: तकनीकी गलती या अंदरूनी राजनीति?

(पेज 1 का शेष)

कांग्रेस के ही कुछ वर्गों में यह चर्चा तेज है कि जब नामांकन प्रक्रिया में अभिषेक मनु सिंघवी और विवेक तन्खा जैसे अनुभवी वकीलों की भूमिका मानी जाती है तो फिर इस तरह की त्रुटि कैसे हो सकती है। हालांकि, इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन राजनीतिक बहसों में यह विषय लगातार उठाया जा रहा है।

नटराजन के विरोध को नहीं समझ पाया आलाकमान

मीनाक्षी नटराजन के नाम की चर्चा होते ही प्रदेश में उनका पार्टी के अंदर अंदरूनी विरोध शुरू हो गया था। क्योंकि नटराजन से ज्यादा काबिल उम्मीदवार प्रदेश में थे। यह विरोध केवल प्रदेश तक सीमित नहीं था बल्कि तेलंगाना में भी था। वह वहां की एनएसयूआई के प्रभारी थी। आलाकमान इस विरोध को समझ ही नहीं पाया। जिसका खामियाजा सीट गंवा के भुगताना पड़ा। आलाकमान को ऐसे मुद्दों पर सबकी रायशुमारी लेनी चाहिए। ऐसे में तो अन्य राज्यों में भी कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज तक के इतिहास में प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ है। पूरी संख्या बल के बाद भी पार्टी ने एक सीट गंवा दी। कांग्रेस ने डमी प्रत्याशी का फॉर्म भी नहीं भरा था। यह भरा होता तो पार्टी की उम्मीदवारी सुरक्षित रह जाती।

भाजपा की भूमिका को लेकर लगाए जा रहे राजनीतिक आरोप

कुछ राजनीतिक चर्चाओं में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम को केवल कांग्रेस की आंतरिक समस्या के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसमें सत्तारूढ़ दल की रणनीतिक भूमिका की संभावना भी तलाश की जा रही है। हालांकि, इन दावों का कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है और यह मुख्यतः राजनीतिक बयानबाजी

“गलती या साजिश?” – दो धड़ों में बंटी चर्चा

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस के अंदर और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच दो प्रमुख मत सामने आ रहे हैं। पहला मत इसे पूरी तरह प्रशासनिक या तकनीकी गलती मानता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार नामांकन प्रक्रिया बेहद जटिल होती है, जिसमें कई दस्तावेजों, प्रमाणपत्रों और फॉर्मेट की बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में किसी भी छोटी चूक के कारण नामांकन रद्द हो सकता है। दूसरा मत इसे केवल गलती मानने से इनकार करता है और इसे पार्टी के आंतरिक विरोध या रणनीतिक संतुलन से जोड़कर देखाता है। इस वर्ग का कहना है कि कांग्रेस के भीतर लंबे समय से विभिन्न गुट सक्रिय हैं और टिकट वितरण या राज्यसभा नामांकन जैसे निर्णयों में अक्सर असंतोष की स्थिति देखने को मिलती है। ऐसे में कुछ लोग इस घटना को “अंदरूनी राजनीति” का परिणाम भी मान रहे हैं।



और अटकलों पर आधारित है। भारतीय राजनीति में यह सामान्य प्रवृत्ति रही है कि किसी भी बड़े नामांकन विवाद या चुनावी असफलता के बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष एक-दूसरे पर रणनीतिक आरोप लगाते हैं। इस मामले में भी इसी तरह की राजनीतिक बयानबाजी सामने आ रही है, लेकिन तथ्यात्मक स्तर पर स्थिति अभी अस्पष्ट बनी हुई है।

कांग्रेस के अंदरूनी समीकरण और राज्यसभा चयन

राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन में अक्सर राजनीतिक संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और गुटिय समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मध्यप्रदेश जैसे राज्य में जहां कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला रहा है, वहां राज्यसभा सीटों का चयन और भी रणनीतिक हो जाता है। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस में इस बात पर भी चर्चा रही है कि क्या राज्यसभा सीट के लिए केवल मध्यप्रदेश के स्थानीय नेताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए या फिर पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को भी

प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। मीनाक्षी नटराजन का नाम इस संदर्भ में इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा था क्योंकि वे पहले भी संगठन और चुनावी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा चुकी हैं।

यहां यह कांग्रेस आलाकमान की रणनीतिक चूक है?

राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग यह मानता है कि यदि नामांकन में किसी प्रकार की त्रुटि हुई है, तो इसे केवल व्यक्तिगत स्तर पर गलती मानना सही नहीं होगा, बल्कि यह संगठनात्मक स्तर पर समन्वय की कमी का संकेत भी हो सकता है। कांग्रेस जैसे बड़े राजनीतिक दल में जब किसी महत्वपूर्ण चुनावी प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट नियंत्रण और निगरानी नहीं होती, तो ऐसे विवाद उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि, पार्टी नेतृत्व की ओर से इस मुद्दे पर कोई विस्तृत टिप्पणी नहीं आई है, जिससे कई सवाल अनुराजित बने हुए हैं।

मीनाक्षी नटराजन की राजनीतिक भूमिका और प्रभाव

(पेज 1 का शेष)

उन्होंने कृषि के आधुनिकीकरण, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन और कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना को राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किए बिना विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता।

जनजातीय विकास को मिली नई गति

मुख्यमंत्री साय ने नीति आयोग के समक्ष विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में संचालित योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार आदिवासी समुदायों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनेक पहल कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कौशल विकास और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वनवासी क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य विकास की मुख्यधारा से दूर रहे क्षेत्रों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ना है ताकि वहां के युवाओं को भी समान अवसर प्राप्त हो सकें।

बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर

बैठक में मुख्यमंत्री ने सड़क, रेल और औद्योगिक अधोसंरचना के विकास को राज्य की प्रगति के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में विभिन्न सड़क परियोजनाओं, औद्योगिक क्षेत्रों और लॉजिस्टिक नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार

नीति आयोग की बैठक में छत्तीसगढ़ मॉडल की गुंज

का प्रयास है कि निवेशकों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया जाए, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित हों और औद्योगिक विकास को गति मिले। उन्होंने बताया कि उद्योगों और स्थानीय रोजगार के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए विशेष रणनीति पर काम किया जा रहा है।

स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार

मुख्यमंत्री साय ने स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि दूरस्थ ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ बनाने, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने और मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य सरकार गुणवत्ता सुधार, डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास आधारित पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगारोन्मुखी शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।

डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शिता

नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री ने डिजिटल

प्रशासन को सुशासन का प्रभावी माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ रही है, जिससे आम नागरिकों को पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं मिल सकें। डिजिटल तकनीक के माध्यम से योजनाओं की निगरानी, लाभार्थियों की पहचान और वित्तीय प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाया गया है। इससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि हुई है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की पहल

मुख्यमंत्री साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों की प्रगति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा और विकास दोनों को समान प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार कार्य कर रही है। सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार योजनाओं के माध्यम से इन क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विकास और जनभागीदारी के माध्यम से इन क्षेत्रों में स्थायी शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा।

विकसित भारत में छत्तीसगढ़ की

भूमिका

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनजातीय विकास जैसे क्षेत्रों में समन्वित प्रयास कर रही है। उन्होंने नीति आयोग से राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सहयोग और संसाधनों के बेहतर समन्वय की अपेक्षा भी व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल ही देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है।

विकास और सुशासन का संदेश

नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रस्तुति ने यह स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ सरकार विकास को केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं मानती, बल्कि उसे सामाजिक न्याय, जनकल्याण और समावेशी प्रगति से जोड़कर देखती है। किसानों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों को विकास प्रक्रिया के केंद्र में रखकर राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। बैठक में प्रस्तुत दृष्टिकोण से यह संदेश भी सामने आया कि छत्तीसगढ़ अपनी सांस्कृतिक पहचान, प्राकृतिक संसाधनों और जनशक्ति को आधार बनाकर विकास की नई संभावनाओं को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। आने वाले वर्षों में इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन राज्य को आर्थिक और सामाजिक रूप से अधिक सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

आवास से उद्योग तक, विकास की अनेक कहानियों के नायक कमलनाथ

(पेज 1 का शेष)

आवास के अधिकार को सम्मान देने वाली सोच

देश के गरीब और वंचित वर्ग को पक्के आवास उपलब्ध कराने की अवधारणा को मजबूती देने में कमलनाथ की भूमिका को अक्सर याद किया जाता है। ग्रामीण भारत में रहने वाले लाखों परिवारों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इंदिरा आवास योजना एक ऐतिहासिक पहल थी। इस योजना का उद्देश्य केवल मकान बनाना नहीं था, बल्कि उन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और आत्मसम्मान प्रदान करना था जो वर्षों से कच्चे घरों और असुरक्षित परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे थे। आज जब केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से "हर व्यक्ति को आवास" के लक्ष्य को आगे बढ़ा रही है, तब यह स्वीकार करना होगा कि इसकी वैचारिक नींव पूर्ववर्ती आवास योजनाओं ने ही तैयार की थी। ग्रामीण आवास के क्षेत्र में जो सोच दशकों पहले विकसित हुई, उसी का विस्तारित स्वरूप आज देश में दिखाई देता है।

विकास को राजनीति का केंद्र बनाने वाले नेता

कमलनाथ का मानना रहा है कि राजनीति का अंतिम उद्देश्य जनता का जीवन बेहतर बनाना होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास किए। देश में औद्योगिक वातावरण को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में उनके कार्यों को उद्योग जगत ने भी सराहा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में रहते हुए उन्होंने भारतीय उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने पर जोर दिया। आर्थिक उदारीकरण के



बाद के दौर में भारत को वैश्विक व्यापारिक व्यवस्था से जोड़ने में उनकी भूमिका उल्लेखनीय मानी जाती है। उनके प्रयासों से निवेशकों का विश्वास बढ़ा और देश के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को गति मिली।

मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास में कमलनाथ का योगदान

वर्ष 2018 में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ ने प्रशासनिक सुधार और निवेश आधारित विकास पर विशेष ध्यान दिया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए 'मैनीफिस्ट मध्य प्रदेश' जैसे आयोजनों और क्षेत्र-विशिष्ट नीतियों पर विशेष जोर दिया।

सरकार ने 'मैनीफिस्ट एमपी' इन्वेस्टर समिट के माध्यम से करीब 32 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव आकर्षित किए, जिसमें कपड़ा क्षेत्र में ही बड़े निवेश की घोषणाएं हुईं। कमलनाथ ने उद्योगपतियों के सामने रखते हुए दो टुक कहा कि उद्योगों को स्थानीय स्तर पर लोगों को 70 फीसदी रोजगार उपलब्ध कराने की शर्त का पालन करना ही होगा। सरकार ने 'वन-साइज-फिट-ऑल' (सभी के लिए एक समान) नीति को बदलते हुए क्षेत्र-विशिष्ट औद्योगिक नीतियां लागू कीं। इसके जरिए टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया। उन्होंने किसानों, युवाओं और उद्योगों को केंद्र में रखकर कई योजनाओं की शुरुआत की। निवेश आकर्षित करने के लिए आयोजित कार्यक्रमों ने प्रदेश

को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई। उनकी सरकार ने औद्योगिक विकास, कृषि क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण और आधारभूत संरचना के विस्तार को प्राथमिकता दी। यद्यपि उनका कार्यकाल अपेक्षाकृत छोटा रहा, फिर भी कई योजनाओं और नीतिगत निर्णयों ने उनकी विकासोन्मुख सोच को प्रदर्शित किया।

संवाद और समन्वय की राजनीति

कमलनाथ की सबसे बड़ी विशेषता उनकी संवाद क्षमता मानी जाती है। राजनीतिक विरोधियों से लेकर उद्योगपतियों, सामाजिक संगठनों और प्रशासनिक अधिकारियों तक, सभी के साथ संवाद स्थापित करने की उनकी क्षमता ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में अलग पहचान दिलाई। वे उन नेताओं में रहे जिन्होंने टकराव की राजनीति के बजाय समन्वय और संवाद के माध्यम से समाधान खोजने का प्रयास किया। यही कारण है कि विभिन्न दलों के नेता भी उनकी राजनीतिक समझ और अनुभव का सम्मान करते रहे हैं।

अनुभव की राजनीति का महत्व

आज जब भारतीय राजनीति तेजी से बदल रही है, तब अनुभवी नेताओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कमलनाथ का लंबा राजनीतिक अनुभव, प्रशासनिक समझ और राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने की क्षमता उन्हें कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं की श्रेणी में स्थापित करती है। संगठनात्मक मजबूती, विकास आधारित राजनीति और प्रशासनिक अनुभव के कारण वे नई पीढ़ी के नेताओं के लिए भी मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकते हैं। कमलनाथ का राजनीतिक जीवन इस बात का उदाहरण है कि विकास, जनकल्याण और प्रशासनिक दक्षता राजनीति की सबसे बड़ी पूंजी हो सकती है। केंद्र सरकार में मंत्री से लेकर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री तक की उनकी यात्रा जनसेवा, विकास और दूरदृष्टि की कहानी कहती है।

छत्तीसगढ़ ने निवेश आकर्षित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि

-शशि पांडे

जगत प्रवाह, रायपुर। हैदराबाद में आयोजित 'छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट' कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की सात प्रमुख कंपनियों ने 9,580 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दिए हैं, जिससे 7,800 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा विकसित भारत के प्रोथ इंजन के रूप में छत्तीसगढ़ तेजी से उभर रहा है और राज्य में निवेशकों के लिए 'रेड कार्पेट' बिछा हुआ है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन सहित दक्षिण भारत के कई बड़े उद्योगपति, निवेशक और कारोबारी प्रतिनिधि मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के साथ-साथ जापान और दक्षिण कोरिया में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य को 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

9,580 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दिए



राज्य सरकार इन प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ आज निवेश के लिए देश के सबसे बेहतर राज्यों में से एक बनकर उभर रहा है। राज्य में उद्योगों के लिए आसान प्रक्रियाएं, सिंगल विंडो व्यवस्था,

बेहतर बुनियादी सुविधाएं और उद्योग अनुकूल नीतियां उपलब्ध हैं। उन्होंने निवेशकों को छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापित करने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हैदराबाद ने आईटी, फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी और एयरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ भी इन क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है और दोनों राज्यों के उद्योगपति एवं उद्यमी मिलकर नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश में ग्रीन स्टील को बढ़ावा देने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल है। ऊर्जा क्षेत्र में राज्य को 3.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे प्रदेश देश के प्रमुख पावर हब के रूप में उभर रहा है। कार्यक्रम में सीएसआईडीसी के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, मुख्यमंत्री के कमिश्नर रितु सैन, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक विश्वेश कुमार, उद्योग विभाग के संचालक प्रभत मलिक एवं अन्य अधिकारी भी शामिल रहे।

हरिद्वार कुंभ मेला- 2027 के लिए 115.61 करोड़ की धनराशि स्वीकृत

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह, देहरादून। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) की कार्यकारी समिति की 70वीं बैठक में हरिद्वार कुंभ मेला-2027 के लिए प्रस्तावित "एकीकृत स्वच्छता, ठोस एवं तरल अपशिष्ट तथा जनस्वास्थ्य प्रबंधन योजना" के लिए 115.61 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। 115.61 करोड़ की लागत वाली यह परियोजना पूर्णतः केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत प्रस्तावित है। परियोजना का उद्देश्य कुंभ मेले के दौरान आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ, सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इस धनराशि से कुम्भ मेले के लिए 13,915 शौचालय, 8,065 यूरिनल तथा 2,000 स्नानगृह स्थापित किए जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 4,840 कूड़ादान, 31.38 लाख लाइनर बैग, 491 अपशिष्ट संग्रहण वाहन, 2 ट्रेश बूम, 15 घाट सफाई मशीनें, 190 स्प्रेडिंग मशीनें एवं ट्रैक्टर, 55 फॉगिंग मशीनें, 30 घास काटने की मशीनें, कौटनाशक, पीपीई किट, प्राथमिक उपचार किट तथा सड़क सफाई हेतु आवश्यक उपभोग्य



सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ट्रांसफर स्टेशन सुविधाओं, गैस आधारित शवदाह गृह तथा फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही निगरानी एवं प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने हेतु क्वाउड-आधारित डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा स्वीकृत की गई धनराशि से हरिद्वार में 2027 में आयोजित होने वाले कुम्भ मेले में स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट तथा जन स्वास्थ्य प्रबंधन के साथ ही निगरानी एवं प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।

सम्पादकीय मध्यप्रदेश की राजनीति विकास, नेतृत्व और चुनौतियों के बीच नया दौर

मध्यप्रदेश की राजनीति इन दिनों एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत के बाद प्रदेश में राजनीतिक समीकरणों, नेतृत्व शैली और विकास की प्राथमिकताओं को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। एक ओर सत्तारूढ़ भाजपा अपनी सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों के आधार पर जनविश्वास को मजबूत करने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस संगठनात्मक पुनर्गठन और जनसरोकारों के मुद्दों के सहारे अपनी राजनीतिक जमीन को पुनः मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। वर्तमान समय में प्रदेश की राजनीति का केंद्र विकास, निवेश, कृषि, रोजगार और आधारभूत संरचना जैसे विषय बने हुए हैं। राज्य सरकार लगातार औद्योगिक निवेश आकर्षित करने, सड़क और सिंचाई परियोजनाओं को गति देने तथा कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट और विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त निवेश प्रस्तावों ने मध्यप्रदेश को निवेश के नए गंतव्य के रूप में स्थापित करने की संभावना को बल दिया है। हालांकि राजनीतिक दृष्टि से सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारकर रोजगार के वास्तविक अवसर सृजित करना है।

कृषि प्रदेश होने के कारण किसानों की अपेक्षाएं भी सरकार से जुड़ी हुई हैं। समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन, सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार और कृषि कल्याण को विभिन्न योजनाएं सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। इसके बावजूद खेती की बढ़ती लागत, मौसम की अनिश्चितता और बाजार मूल्य जैसे विषय किसानों की चिंता बने हुए हैं। आने वाले समय में सरकार की सफलता इस बात से भी आंकी जाएगी कि वह कृषि क्षेत्र की इन चुनौतियों को कितना प्रभावी समाधान प्रस्तुत कर पाती है। राजनीतिक परिदृश्य का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष विपक्ष की स्थिति है। कांग्रेस अभी भी प्रदेश में अपनी खाई हुई राजनीतिक ताकत को पुनः प्राप्त करने के प्रयास में लगी हुई है। संगठनात्मक स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और सरकार को जनहित के मुद्दों पर धरने की रणनीति दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस के सामने

सबसे बड़ी चुनौती मजबूत नेतृत्व, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार और जनविश्वास की पुनर्स्थापना है। प्रदेश की राजनीति में प्रभावी विपक्ष का होना लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक माना जाता है।

इन सबके बीच एक और महत्वपूर्ण विषय राजनीतिक संवाद की गुणवत्ता का है। हाल के वर्षों में प्रदेश की राजनीति में व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप और तीखी बयानबाजी का स्तर बढ़ा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वैचारिक मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन राजनीतिक दलों और नेताओं की जिम्मेदारी यह भी है कि सार्वजनिक विमर्श की गरिमा बनी रहे। जनता आज केवल राजनीतिक विवाद नहीं, बल्कि समस्याओं के समाधान और विकास के ठोस परिणाम देखना चाहती है। मध्यप्रदेश की राजनीति में युवा वर्ग भी एक महत्वपूर्ण कारक बनकर उभर रहा है। रोजगार, शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता से जुड़े मुद्दे युवाओं की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। सरकार और विपक्ष दोनों के लिए यह वर्ग भविष्य की राजनीति का निर्णायक आधार बन सकता है। इसी प्रकार महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी भी प्रदेश की राजनीति को नई दिशा दे रही है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं रह गया है। निवेश, अपभ्रंश, कृषि, सामाजिक कल्याण और सांस्कृतिक पहचान जैसे विषय राजनीतिक विमर्श के केंद्र में हैं। जनता अब घोषणाओं से अधिक परिणामों को महत्व देती है। इसलिए सरकार के लिए विकास के बावों को धरातल पर उतारना और विपक्ष के लिए रचनात्मक विकल्प प्रस्तुत करना समय की मांग है। अंततः मध्यप्रदेश की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ अवसर भी है और चुनौतियाँ भी। यदि राजनीतिक दल विकास, सुरासन और जनभागीदारी को प्राथमिकता देते हैं तो प्रदेश आने वाले वर्षों में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकता है। लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति भी इसी में निहित है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जनता के जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम बने, न कि केवल सत्ता प्राप्त का साधन।

सियासी गहमागहमी

मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द होना : साजिश या गलती?

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द होने की घटना ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। सवाल यह उठ रहा है कि यह केवल तकनीकी त्रुटि का मामला है या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है। हालांकि बिना आधिकारिक जांच और तथ्यों के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, लेकिन यह घटना निश्चित रूप से कई सवाल खड़े करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नामांकन प्रक्रिया चुनावी प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। ऐसे में किसी वरिष्ठ नेता का पर्चा निरस्त होना सामान्य घटना नहीं माना जा सकता। यदि नामांकन में दस्तावेजी या प्रक्रियागत कमी रही है, तो यह संबंधित पक्ष की लापरवाही का विषय है। वहीं यदि सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद पर्चा निरस्त किया गया है, तो निष्पक्ष जांच की आवश्यकता और बढ़ जाती है। राजनीतिक दल इस मुद्दे को अपने-अपने नजरिए से देख रहे हैं। कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े प्रश्न के रूप में उठा सकती है, जबकि प्रशासनिक पक्ष इसे नियमों के पालन का मामला बता सकता है। ऐसे समय में सबसे जरूरी है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे और तथ्य सार्वजनिक किए जाएं।

अब नाराज भाजपा नेताओं को कैसे मजाएगा मद्राज भाजपा संगठन?

मध्यप्रदेश भाजपा के सामने इन दिनों संगठनात्मक संतुलन बनाए रखने की चुनौती दिखाई दे रही है। सत्ता और संगठन में जिम्मेदारियों के वितरण के बाद कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी समय-समय पर सामने आती रही है। ऐसे में पार्टी नेतृत्व के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता नाराज नेताओं को सम्मानजनक संवाद और उचित भूमिका देकर साथ बनाए रखना होगी। भाजपा की ताकत हमेशा उसके मजबूत संगठन और सामूहिक नेतृत्व की संस्कृति रही है। पार्टी नेतृत्व जानता है कि चुनावी सफलता के लिए केवल सरकार का प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं का मनोबल भी महत्वपूर्ण होता है। यही कारण है कि संगठन अक्सर संवाद, समन्वय और जिम्मेदारियों के पुनर्वितरण के माध्यम से असंतोष को कम करने का प्रयास करता है। आने वाले समय में संगठन को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुभवी नेताओं की उपेक्षा की भावना न बने और नई पीढ़ी को भी पर्याप्त अवसर मिले। यदि भाजपा यह संतुलन साधने में सफल रहती है, तो नाराजगी को संगठनात्मक ऊर्जा में बदलना उसके लिए कठिन नहीं होगा।

हपते का कार्टून



ट्वीट-ट्वीट

असम में वायुसेना की विमान दुर्घटना ने हमारे पाँच वीर जवानों के शहीद होने का समाचार अत्यंत दुःखद है।

इस दुःख की घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं शहीदों के शोककुल परिजनों के साथ हैं। देश इन बहादुर जवानों का सवीच बलिदान हमेशा याद रखेगा।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता

@RahulGandhi



भाजपा सरकार वोट चोरी और शीट चोरी के बाद अब गाँव चोरी पर उतर आती है। झारखण्ड जिले में एक आदिवासी बहुल गाँव को राज्य के रिजर्व से बाहर कर दिया है। यहाँ के किसानों को किसान ही नहीं माना जा रहा है। उन्हें न तो किसान सम्मान निधि मिल रही है, न फसल बीमा और न किसान ऋण मिल रहा है।

-कमलनाथ

पट्टे काबूट अरव्य

@OfficeOfKNath



राजवीरों की बात

तरुण चुग: संगठन, समर्पण और राष्ट्रवाद की राजनीति का सशक्त चेहरा

समता पाठक/जगत प्रवाह



भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में जिन नेताओं ने संगठनात्मक क्षमता, वैचारिक प्रतिबद्धता और जमीनी कार्यशैली के बल पर अपनी अलग पहचान बनाई है, उनमें तरुण चुग का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में

राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले तरुण चुग आज भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। संगठन के प्रति उनकी निष्ठा, कार्यकर्ताओं से संवाद की क्षमता और पार्टी की विचारधारा के प्रति समर्पण ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में विशिष्ट स्थान दिलाया है। तरुण चुग का जन्म 18 नवंबर 1971 को पंजाब के अमृतसर में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर में ही प्राप्त करने के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा हॉसिल की और युवावस्था से ही सामाजिक एवं राष्ट्रवादी गतिविधियों से जुड़े गए। छात्र जीवन में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) से जुड़े, जिसने उनके नेतृत्व कौशल को निखारने और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया। एबीवीपी में रहते हुए उन्होंने युवाओं के बीच संगठन निर्माण, राष्ट्रहित और सामाजिक जागरूकता के विभिन्न अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाई।

राजनीतिक जीवन में उनकी वास्तविक पहचान भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्यों से बनी। उन्होंने भाजपा युवा मोर्चा में विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और धीरे-धीरे पार्टी नेतृत्व का विश्वास अर्जित किया। पंजाब जैसे राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण राज्य में भाजपा के संगठन को मजबूत बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वे लंबे समय तक पंजाब भाजपा के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे और पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करते रहे। तरुण चुग की सबसे बड़ी विशेषता उनकी संगठनात्मक क्षमता मानी जाती है। वे उन नेताओं में हैं जो केवल मंचीय राजनीति तक सीमित नहीं रहते, बल्कि बृथ स्तर तक कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाए रखते हैं। भाजपा के विस्तार अभियान में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। पार्टी नेतृत्व ने समय-समय पर उन्हें विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी, जहां उन्होंने संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का कार्य किया।

वर्ष 2020 में भाजपा ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया। यह जिम्मेदारी उनके लंबे संगठनात्मक अनुभव और नेतृत्व क्षमता का प्रमाण थी। राष्ट्रीय महासचिव के रूप में उन्होंने विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन को सुदृढ़ बनाया, चुनावी रणनीतियों के क्रियान्वयन तथा कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में पार्टी की गतिविधियों के समन्वय की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में तरुण चुग का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भाजपा की नीतियों और विकास योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। वे अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई और राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर पार्टी का पक्ष प्रभावशाली ढंग से रखते रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार तरुण चुग उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। उनकी कार्यशैली में अनुशासन, संवाद और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण स्पष्ट दिखाई देता है। वे युवा कार्यकर्ताओं को राजनीति में सकरात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करते हैं और भाजपा की वैचारिक परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में सक्रिय रहते हैं।

तरुण चुग का सार्वजनिक जीवन केवल राजनीति तक सीमित नहीं है। वे सामाजिक सरोकारों से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी सक्रिय रहते हैं। शिक्षा, युवाओं के कौशल विकास, राष्ट्र निर्माण और सामाजिक समरसता जैसे विषय उनके सार्वजनिक वक्तव्यों में प्रमुखता से दिखाई देते हैं। उनकी पहचान एक ऐसे नेता के रूप में बनी है जो संगठन की मजबूती को राजनीतिक सफलता की आधारशिला मानते हैं। आज तरुण चुग भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने कार्यकर्ता से राष्ट्रीय नेतृत्व तक की यात्रा अपने परिश्रम, समर्पण और संगठनात्मक कौशल के बल पर तय की है। उनका राजनीतिक जीवन इस बात का उदाहरण है कि विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता, निरंतर परिश्रम और संगठन के प्रति समर्पण किसी भी कार्यकर्ता को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा सकता है। भाजपा के संगठनात्मक विस्तार और राष्ट्रवादी राजनीति को मजबूत करने में उनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है।

लेदर बाल क्रिकेट प्रतियोगिता में हरदा ने टिमरनी को पराजित किया



-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। नगर के एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल के खेल मैदान में चल रहे लेदर बॉल क्रिकेट कैंप के अंतर्गत हरदा प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला टिमरनी और हरदा के बीच खेला गया। इस मुकाबले में हरदा ने टॉस जीतकर टिमरनी को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। टिमरनी ने निर्धारित 20 ओवर में 162 रन बनाए। टिमरनी की ओर से सलामी जोड़ी के रूप में अनुज अग्रवाल और रौनक दोगने ने टीम को अच्छी शुरुआत दी। रौनक दोगने ने 46 रन की सृष्टि बूझ भरी पारी खेली। इसके बाद

कृष्णा पटवारी ने मात्र 41 गेंदों में 86 रनों की जोरदार पारी खेली। कृष्णा ने अपनी इस पारी में 9 छक्के और 4 चौके लगाए। 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हरदा की शुरुवात काफी निराशाजनक रही। ओपनिंग बल्लेबाज संचित पांडे मात्र 2 रन बनाकर आउट हो गए। संचित को टिमरनी के तेज गेंदबाज प्रकल्प तिवारी ने बॉल्ड आउट किया। इसके पश्चात हरदा की ओर खेल रहे यथार्थ डूडी ने अपनी 92 रनों की मैच जिताऊ पारी से टिमरनी के अरमानों पर पानी फेर दिया। टिमरनी के कृष्णा पटवारी को 86 रन बनाने के साथ 2 विकेट लेने पर यथार्थ डूडी के साथ संयुक्त रूप से प्लेयर ऑफ द मैच

का पुरस्कार दिया गया। टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी करने वाले रौनक दोगने को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दिया गया। हरदा के कुलदीप सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बने। मैच में मुख्य अतिथि के रूप में टिमरनी के नायब तहसीलदार दीपक सिंह, चंदन शांगुल्ये, निमिष गर्ग, उपकार गोहिया, राकेश भिलाला, तिनका सामाजिक सेवा संस्थान की ओर से रितेश तिवारी, राजेश कौशल, नरेंद्र सोलंकी एवं अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। सभी पुरस्कार समारण के अवसर पर मुख्य अतिथि नायब तहसीलदार दीपक सिंह के द्वारा प्रदान किए गए।

12 वर्ष के सिंहस्थ जैसा प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल: सीएम डॉ. मोहन यादव

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. गोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र के 12 साल पूरे होने के मौके पर कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मीडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं संवाद समारोह के दौरान सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा- हमारे यहां 12 वर्ष का महत्व है। 12 वर्ष में सिंहस्थ होता है। स्मार्ट सिटी के फैसे से बाबा महाकाल का महालोक बना दिया। एक संकल्प से धार्मिक पर्यटन का बढ़ा बदलाव आया। नरेंद्र मोदी लगातार 25 साल से सीएम और पीएम के रूप में सेवा का कार्य कर रहे हैं। 12 वर्ष प्रति बारह का अंक हमारे लिए उत्साहवर्धक है। सिंहस्थ भी बारह वर्ष में ही होता है। जीआईएस हमने भोपाल में आयोजित कर नया कीर्तिमान



बनाया। न्याय प्रणाली में भारतीयता का तत्व वापस आया है। 18 वर्षों तक देश सेवा का अवसर मिला

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा- प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्रियों में शामिल हैं। अब तक 4402 दिनों से देश का नेतृत्व कर रहे

हैं। भाजपा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को धरातल पर उतारा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के छह वर्ष और प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्षों को मिलाकर भाजपा को केंद्र में 18 वर्षों तक देश सेवा का अवसर मिला है। इस अवधि में विचारधारा, सुशासन और अंत्योदय के संकल्प को साकार करने का प्रयास किया गया है।

शासन को जनसेवा का माध्यम बनाया

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने शासन को जनसेवा का माध्यम बनाया है। एक गरीब के आंसू कैसे पोंछे जाएं, यह देश को प्रधानमंत्री मोदी ने सिखाया है। विकास के हर क्षेत्र में केंद्र ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी मौजूद रहे।

सात दिवसीय श्रीमद भागवत महापुराण संपन्न

-संवाददाता

जगत प्रवाह, गौपाल। शिक्षक कांग्रेस कॉलोनी, रामजानकी मंदिर, भेल संगम चौराहा भोपाल में आयोजित सात दिवसीय श्रीमद भागवत महापुराण संपन्न हो गया है। श्रीमद भागवत महापुराण 08 जून से 14 जून 2026 तक आयोजित किया गया। मुख्य कथा वाचक श्री पं. धर्मन्द्राचार्य जी महाराज, श्री वृन्दावन धाम (जोनतला) थे। इनके मुखारबिंदु से श्रीमद भागवत महापुराण का वाचन किया गया। इस अवसर पर सहायक के रूप में पं. राकेश बसेडिया भोपाल विशेष रूप से उपस्थित रहे।



भारत की बढ़ती परमाणु शक्ति

सिपरी यानी स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान की ताजा रिपोर्ट में भारत की बढ़ती परमाणु शक्ति को रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियार मोर्चे पर तैनात किए हैं। जबकि भारत के पास कुल परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर लगभग 190 हो गई है। भारत ने 2025 में सैन्य खर्च 92.1 अरब डॉलर किया है। इस कारण भारत दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा सैनिक हथियारों पर खर्च करने वाला देश बन गया है।

हथियार आयात करने में भी भारत दूसरे स्थान पर है। इस कड़ी में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर रूस, तीसरे पर चीन, चौथे पर भारत और पांचवें पर पाकिस्तान है। दुनिया के पास कुल 12,187 परमाणु हथियार हैं। इनमें सबसे ज्यादा अमेरिका के पास 5042 हथियार हैं। सिपरी के अनुसार भारत लंबी दूरी के हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है, ताकि पूरे



प्रमोद भार्गव
वीरध पत्रकार

है। यह बात ट्रंप ने न्यूज चैनल सीबीएस से बात करते हुए कही थी। दरअसल रूस द्वारा ट्रंप से पूछा गया था कि 'क्या वे एडवॉंस न्यूक्लियर-कैपेबल सिस्टम, जिसके द्वारा पोसाइडन अंडरवाटर ड्रोन गतिविधि शामिल है, उसके परीक्षण के बाद परमाणु हथियारों का परीक्षण भी करेंगे?' इसके उत्तर में ट्रंप ने कहा था, 'उनके पास किसी भी दूसरे देश से अधिक परमाणु हथियार

सकता है। ये ड्रोन पनडुब्बी वाहनों के समान होते हैं, जो बिना किसी मानव के पानी के नीचे संचालन और अनुसंधान के लिए होते हैं। किसी भी परमाणु हथियार संज देश को परमाणु परीक्षण की जरूरत इसलिए होती है, क्योंकि परमाणु बम के लिए जरूरी यूरैनियम को संवर्धन (एनरिच) करना होता है। यह प्रक्रिया एक तकनीकी परीक्षण है। परमाणु परीक्षण की घोषणा किसी भी देश की ऐसी यौद्धिक रणनीति का हिस्सा है, जिससे वह शत्रु देश को अपनी ताकत का अहसास कराता है। भारत ने 1998 के बाद कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है। अब चीन और

ट्रंप को कहना पड़ा है कि 'ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के विरुद्ध भारत परमाणु हमले के लिए तत्पर था। इस कारण पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मुझे निवेदन किया था कि आप बीच में आकर युद्ध रोकें, वरना पाक में लाखों लोग मारे जाएंगे।' बहरहाल, ट्रंप के किसी भी दावे की पुष्टि भारत नहीं करता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि दुनिया के कई देश न केवल परमाणु परीक्षण करने में लगे हैं, बल्कि घातक परमाणु हथियारों को इकट्ठा करने की होड़ में भी लगे हैं। स्टॉकहोम स्थित 'अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान' (एसआईआरआई) के एक

का बड़ा जखीरा है। चीन परमाणु हथियारों की संख्या के बढ़ाने के साथ उनका तकनीकी रूप से आधुनिकीकरण भी कर रहा है। सकूदी अरब, मिश्र, भारत, आस्ट्रेलिया और चीन ने 2016 से 2020 के बीच सबसे ज्यादा हथियार आयात किए हैं। ट्रंप तो सरेआम कह रहे हैं कि उनके पास दुनिया को 150 बार तहस-नहस करने की परमाणु क्षमता है। यानी दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईए के पूर्व वरिष्ठ खुफिया अधिकारी केविन हलबर्ट की बात मानें तो पाकिस्तान दुनिया के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक देशों में से एक है। पाकिस्तान की यह खूंखार और डरावनी सूरत इसलिए बन गई है, क्योंकि तीन तरह के जोखिम इस देश में खतरनाक ढंग से बढ़ रहे हैं। एक आतंकवाद, दूसरे ढह रही अर्थव्यवस्था और तीसरे परमाणु हथियारों का जरूरत से ज्यादा भंडारण। आर्थिक संकट के ऐसी ही बदतर हालात से उत्तर कोरिया जूझ रहा है। मानव स्वभाव में प्रतिशोध और ईर्ष्या दो ऐसे तत्व हैं, जो व्यक्ति को विवेक और संयम का साथ छोड़ देने को मजबूर कर देते हैं। इस स्वभाव को क्रूरतम परिणति में बदलते हम अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर किए परमाणु हमलों के रूप में देख चुके हैं। अमेरिका ने हमले का जघन्य अपराध उस नाजुक परिस्थिति में किया था, जब जापान इस हमले के पहले ही लगभग पराजय स्वीकार कर चुका था। पाक इस समय इसी क्रूरतम मानसिकता से गुजर रहा है। ऐसे में यदि वह चीन के साथ परमाणु परीक्षण कर रहा है, तो यह बेहद चिंताजनक स्थिति है। ट्रंप जो बात कह रहे हैं, वह हवा-हवाई होने की बजाय संभव है कि उनकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर कही गई हो? ट्रंप जैसे अविवेकी शासक पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है।



हथियारों की ताकत टटोल रहे हैं। ये देश कभी भी यह बात स्वीकारने को तैयार नहीं हैं कि वे परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। ये देश भूमि की बहुत गहराई में परीक्षण करते हैं। इसलिए इनके परीक्षण की आहट किसी के कानों में नहीं गुंजती है। इन देशों के लोग खुले समाज के हिस्सा नहीं हैं, अतएव यहां की जानकारियां गोपनीय बनी रहती हैं। यह बात ट्रंप को इसलिए कहनी पड़ी, क्योंकि अमेरिका 30 साल बाद अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर से करने का फैसला ले चुका है। इसलिए उन्होंने अपनी सरकार के फैसले को पाक और चीन के परीक्षणों के परिप्रेष्य में ताकिक ठहराने के लिए कही

हैं। इन हथियारों से दुनिया को 150 बार नष्ट किया जा सकता है। हम इन्हें नहीं परखते। किंतु जब दूसरे देश परीक्षण कर रहे हैं, तब हमें भी करने की जरूरत है।' याद रहे, ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के बसान नगर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने से पहले अमेरिका द्वारा परमाणु परीक्षणों को फिर से शुरू करने का बयान दिया था। पानी के भीतर पोसाइडन ड्रोन प्रणाली एक ऐसी तकनीक है, जिसमें रोबोटिक वाहन पानी के नीचे सक्रिय रहते हैं। ये स्वायत्त रूप से संचालित रहने के साथ इन्हें रिमोट के जरिए दूर से भी संचालित किया जा

सकता है। ये ड्रोन पनडुब्बी वाहनों के समान होते हैं, जो बिना किसी मानव के पानी के नीचे संचालन और अनुसंधान के लिए होते हैं। किसी भी परमाणु हथियार संज देश को परमाणु परीक्षण की जरूरत इसलिए होती है, क्योंकि परमाणु बम के लिए जरूरी यूरैनियम को संवर्धन (एनरिच) करना होता है। यह प्रक्रिया एक तकनीकी परीक्षण है। परमाणु परीक्षण की घोषणा किसी भी देश की ऐसी यौद्धिक रणनीति का हिस्सा है, जिससे वह शत्रु देश को अपनी ताकत का अहसास कराता है। भारत ने 1998 के बाद कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है। अब चीन और

अध्ययन ने दावा किया है कि चीन के पास 350, पाकिस्तान 165 और भारत के पास जनवरी 2021 तक 156 परमाणु हथियार मौजूद थे। हालांकि ताजा रिपोर्ट के अनुसार सभी देशों ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या में वृद्धि कर ली है। ऐसा लगता है कि ये तीनों पड़ोसी देश अपने परमाणु शस्त्रागारों का विस्तार कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस समय 12,187 परमाणु हथियार दुनिया के देशों के पास हैं। इनमें 90 प्रतिशत से ज्यादा रूस और अमेरिका के पास है। इनके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और उत्तर कोरिया के पास भी हथियारों

पर्यावरण की फिक्र



डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद

बाँधों के साये में उदास नदियाँ

हजारों वर्षों तक नदियाँ स्वतंत्र रूप से बहती रहीं और उनके तटों पर मानव बस्तियाँ और संस्कृति विकसित हुई। परंतु आधुनिक विकास ने नदी के खदक प्रवाह को बांधों, बैराजों और जलाशयों के माध्यम से बाँध दिया है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रति मानवीय हस्तक्षेप ने वर्षों से विशाल परिवर्तन किए हैं। नदियों, जो कि जीवन के स्रोत हैं, उन्हें बांधों के निर्माण से उनके मूल प्रवाह में अक्षय पैदा कर दिया गया। यह एक ऐसा विषय है जिस पर व्यापक चर्चा की जरूरत है, और आज हम इसे अपने स्तर में उठा रहे हैं। नदियाँ

शिरफ़ जल का स्रोत ही नहीं अपितु ये जीवन का आधार भी हैं। आज दुनिया के अरबों लोग नदियों पर निर्भर हैं। लेकिन अधिकांश बड़ी नदियों को आज या तो बांध अथवा तटबंध बनाकर ही बाँध दी गई है या वह इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि उनकी अस्तित्व ही खतरे में आ गई है। कुछ वर्ष पहले जर्मन नेचर ने प्रकाशित अररयन से पता चला था कि दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से लगभग दो तिहाई नदियों की बांधों, तटबंधों, जलाशयों एवं मनुष्यों द्वारा निर्मित अन्य संरचनाओं ने नुकसान पहुंचाया गया।

बांध बनाने का मुख्य उद्देश्य जल भंडारण, सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन रहा है। ये सभी महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन्होंने विकास को संभव बनाया है। परंतु, इसके साथ ही, नदियों के अचिरल प्रवाह में बाधा और पारिस्थितिकी तंत्र पर दीर्घकालिक प्रभाव उत्पन्न हुए हैं। जैव विविधता में कमी, मछलियों के प्रजनन में बाधा और नदी के किनारे के समुदायों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

विश्व भर में, नदियों को उनके मूल स्वरूप में बहाल करने की दिशा में पहल की जा रही है। इसमें बांधों को ध्वस्त करना और नदी को उसके प्राकृतिक मार्ग में बहने देना शामिल है। यूरोप में नदियों को अचिरल धारा के लिए मुहिम चल रही है। साल 2016 से ही बांध तोड़े जा रहे हैं। 2022 में ही यूरोपीय नदियों पर बने 325 बांध तोड़ दिए गए, जो 2021 से 36% ज्यादा है। खास बात यह है कि जिन नदियों पर बांध तोड़े गए वहां का जलीय जीवन बदलने लगा है। फिनलैंड हिटोलॉजिक नदी में सोलोमोन जैसी मछलियाँ नजर आने लगी, जो सालों पहले खत्म हो चुकी थीं। फिनलैंड की नैचुरल रिसोर्स इन्स्टीट्यूट की इकोलॉजिस्ट पॉलिना का कहना है कि मछलियों का लौटना इस बात की निशानी है कि नदी का इकोसिस्टम खुद को ठीक कर रहा है। स्थानीय पौधे दोबारा उगने लगे। पर्यावरण परिवर्तन कम करने के लिए नदियों को उनके नैसर्गिक पर्यावरण में रहने देने की कोशिश की जा रही है। यूरोप से पहले अमेरिका ने अपनी

नदियों से बांध हटाने की शुरुआत की। वहां 2000 से ज्यादा बांध तोड़ दिए गए। जिन नदियों के बांध तोड़े गए वहां का पर्यावरण तेजी से बदलने लगा और नदी अपने स्वरूप में आने लगी और साथ साथ हरियाली भी बढ़ी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करना और जलीय जीवन को पुनर्जीवित करना है।

हमें यह समझना होगा कि नदियाँ केवल पानी का स्रोत नहीं हैं, बल्कि वे एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो विभिन्न प्रजातियों का घर हैं। नदियों के अचिरल प्रवाह से, प्राकृतिक जल चक्र को समर्थन मिलता है, जिससे वर्षा जल संचयन और भूजल स्तर को बढ़ावा मिलता है। इससे जल संकट की समस्या में कमी आ सकती है, जो कि आज के समय में एक बड़ी चिंता है।

यह समय है जब हमें विकास और पारिस्थितिकी संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। बांधों को ध्वस्त करना और नदियों को उनके प्राकृतिक प्रवाह में बहने देना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इससे न केवल जलीय जीवन को बल मिलेगा, बल्कि यह हमारे पर्यावरण के संरक्षण में भी योगदान देगा। अंत में, हम सभी को यह समझना होगा कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सतत विकास हमारे सामूहिक भविष्य के लिए आवश्यक है। नदियों को उनके प्राकृतिक प्रवाह में बहने देना, इस दिशा में एक जरूरी कदम है। आइए हम सभी मिलकर इस दिशा में काम करें और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखें।

आज की बात



प्रवीण कुलकर्णी
सूत्रज्ञ लेखक

बारिश की हर बूंद बने भविष्य की पूंजी

पहली बारिश की सोंधी खुशबू हर मन को आनंद से भर देती है। भारत में मानसून केवल एक मौसम नहीं, बल्कि जीवन का उत्सव है। लेकिन इस उत्सव के पीछे एक ऐसा कड़वा सच छिपा है, जिसे हम हर साल नजरअंदाज कर देते हैं। जिस अमृत रूपी जल का हम महीनों इंतजार करते हैं, उसका बड़ा हिस्सा कुछ ही घंटों में नालियों के रास्ते बहकर व्यर्थ चला जाता है। फिर कुछ ही महीनों बाद हम पानी के लिए चिंतित दिखाई देते हैं। सवाल बारिश कम होने का नहीं, बल्कि बारिश के पानी को सहेजने की हमारी सोच और व्यवस्था का है। भारत आज गंभीर जल संकट की चुनौती का सामना कर रहा है। नीति आयोग की 'कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स' रिपोर्ट के अनुसार देश की लगभग 60 करोड़ आबादी जल संकट से प्रभावित है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट चेतावनी देती है कि यदि वर्तमान गति से भूजल का दोहन जारी रहा, तो अगले दो दशकों में देश के 60 प्रतिशत ब्लॉक 'क्रिटिकल' श्रेणी में पहुंच सकते हैं। इसका अर्थ है कि पीने के पानी का संकट और गहरा होगा।

स्थिति की गंभीरता को नासा के GRACE सैटेलाइट अध्ययन भी रेखांकित करते हैं। इस अध्ययन के अनुसार भारत का उत्तर-पश्चिम और मध्य क्षेत्र, जिसमें मालवा अंचल भी शामिल है, दुनिया के उन क्षेत्रों में है जहां भूजल स्तर सबसे तेजी से गिर रहा है। वहीं केंद्रीय भूजल बोर्ड की 'डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स' रिपोर्ट बताती है कि देश के लगभग 14 प्रतिशत आकलित ब्लॉक 'ओवर-एक्सप्लॉइटेड' हो चुके हैं, अर्थात् जितना पानी जमीन में पहुंचता है, उससे कहीं अधिक निकाला जा रहा है। मध्यप्रदेश भी इस चुनौती से अछूता नहीं है। मालवा और निमाड़ क्षेत्र में गर्मियों के दौरान भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में भी जल उपलब्धता भविष्य की बड़ी चिंता बनती दिखाई दे रही है। बढ़ती आबादी, कंक्रीट के फैलते जंगल, सिकुड़ते तालाब और वर्षा जल का सीधे नालों में बह जाना इस संकट को और गंभीर बना रहा है।

विडंबना यह है कि जिस समस्या का समाधान हर साल आसमान से बरसता है, उसे हम स्वयं बहा देते हैं। वर्षा जल संचयन कोई जटिल या महंगी तकनीक नहीं, बल्कि जल सुरक्षा का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। विशेषज्ञों के अनुसार 1000 वर्गफीट की एक सामान्य छत पर होने वाली वर्षा को सालभर में लगभग 60 से 70 हजार लीटर पानी संग्रहित या भूजल में पुनर्भरित किया जा सकता है। यह एक औसत परिवार की कई महीनों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त है।

केवल बैंक बैलेंस नहीं, जल बैलेंस भी जरूरी

हम अपने बच्चों के लिए मकान, जमीन, गाड़ियाँ और बैंक बैलेंस छोड़ने की चिंता करते हैं लेकिन यदि उनके हिस्से में पर्याप्त और स्वच्छ पानी नहीं होगा, तो बाकी सारी संपत्ति का महत्व कम हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी को केवल शिक्षित नहीं, बल्कि जल-साक्षर बनाना होगा। उन्हें यह समझाना होगा कि पानी सुविधा नहीं, जीवन का आधार है और उसका संरक्षण हमारी साझा जिम्मेदारी है। जल संकट का समाधान केवल सरकारों या प्रशासन के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। जिस तरह स्वच्छता जनभागीदारी से जन आंदोलन बनी, उसी तरह जल संरक्षण को भी जन अभियान बनाना होगा। हर घर, हर संस्था और हर नागरिक को इसमें अपनी भूमिका निभानी होगी।

समय आ गया है संकल्प लेने का

मानसून हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। बादल फिर हमारी छतों पर अमृत बरसाने को तैयार हैं। अब फेसला हमारे हाथ में है क्या हम इस अनमोल धरोहर को यूँ ही बहा जाने देंगे या इसे सहेजकर अपने भविष्य को सुरक्षित करेंगे? याद रखिए, पानी की हर बूंद केवल आज की जरूरत नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की पूंजी है। इस मानसून एक संकल्प लें। बारिश की एक भी बूंद व्यर्थ नहीं जाने देंगे। क्योंकि भविष्य उन्हीं का सुरक्षित होगा, जो आज पानी बचाने का निर्णय लेंगे।

जनगणना कार्य में लगे मास्टर ट्रेनर, पर्यवेक्षक एवं प्रणकों का मानदेय अब तक लंबित

-बद्रीप्रसाद कौरव
उगत प्रवाह. नरसिंहपुर। जनगणना को देश की विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी नीतियों का आधार माना जाता है। इसके लिए शासन द्वारा व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण एवं मैदानी कार्य कराए गए, जिनमें मास्टर ट्रेनर, पर्यवेक्षक, प्रणक तथा अन्य सहयोगी कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किंतु जनगणना से जुड़े अनेक कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें आज तक उनके प्रशिक्षण एवं कार्य का मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है।
जानकारी के अनुसार स्वगणना, मकान गणना एवं अन्य जनगणना संबंधी कार्यों के लिए विभिन्न चरणों में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण प्रदान करने वाले मास्टर ट्रेनरों से लेकर मैदानी स्तर पर कार्य करने वाले पर्यवेक्षकों और प्रणकों ने भीषण गर्मी में घर-घर जाकर निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण किया। इसके बावजूद उनके मानदेय का भुगतान लंबित बताया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि प्रशिक्षण अर्वाधि का भुगतान प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद किया जाना था, लेकिन कई माह बीत



जाने के बाद भी राशि उनके खातों में नहीं पहुंची है। उनका कहना है कि जनगणना कार्य के दौरान आवागमन एवं अन्य आवश्यक खर्च उन्होंने स्वयं वहन किए, जिससे आर्थिक बोझ भी बढ़ा है। कर्मचारियों ने सवाल उठाया है कि जब कार्यों को समय पर पूरा कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर लगातार दबाव बनाया जाता है, तो कार्य पूर्ण होने के बाद भुगतान प्रक्रिया में इतनी देरी क्यों की जा रही है।
उनका कहना है कि जिले में जनगणना का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, लेकिन प्रशिक्षण दाताओं, पर्यवेक्षकों एवं प्रणकों के मानदेय भुगतान को लेकर अब तक स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आई है। कर्मचारियों ने जिला प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि लंबित मानदेय का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनगणना कार्य में योगदान देने वाले कर्मचारियों को उनके परिश्रम का उचित प्रतिफल समय पर मिल सके। उनका कहना है कि समय पर भुगतान न होना प्रशासनिक उदासीनता का परिचायक है और इससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है।



नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री



डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के उत्कृष्ट क्रियान्वयन में

देश में प्रथम



98.04%
ग्राउंडिंग के साथ
देश में प्रथम

10 लाख⁺
आवास स्वीकृत

9 लाख⁺
आवास पूर्ण एवं
हितग्राहियों को
वितरित



**पक्का घर बन रहा है
सशक्त और सुरक्षित जीवन का आधार**

अपने सपनों का घर पाने के लिए आज ही ऑनलाइन आवेदन करें।
अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.pmay-urban.gov.in

स्केन QR कोड



नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्यप्रदेश

f x @ in @pmayurbanmp

